'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2016
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 31.01.2016
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 19 ● अंक 5 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 16 से 31 जनवरी, 2016

उत्तर पश्चिम दिल्ली लोक सभा क्षेत्र ने मनाया डॉ0 उदित राज का जन्मदिवस

डॉ0 उदित राज, सांसद, उत्तर पश्चिम दिल्ली लोक सभा क्षेत्र एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, का जन्मदिवस 26 जनवरी, 2016 को लॉन 1, शक्ति फार्म, कंझावला रोड, दिल्ली में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रातः 11 बजे से ही क्षेत्र के लोगों का आगमन शुरू हो गया और 12:30 बजे तक शक्ति फार्म का यह लॉन लोगों से खचाखच भर गया। 24 जनवरी, 2016 को दिल्ली में अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का राष्ट्रीय सेमिनार था, जिसमें देश के कोने-कोने से परिसंघ के नेतागण एकत्रित हुए थे, जिसमें से सैकड़ों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रूके हुए थे। वे भी 12 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। लगभग 1 बजे कार्यक्रम स्थल पर डॉ0 उदित राज जी का आगमन हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। इसके पश्चात् क्षेत्र के गणमान्य लोगों और परिसंघ के नेताओं द्वारा फूलमालाओं से स्वागत कर डॉ0 उदित राज को जन्मदिवस की शुभकनाएं देने की जैसे होड़ लग गयी।

जन्मदिवस के अवसर पर काटने की तैयारी में डॉ0 उदित राज, साथ खड़ी श्रीमती सीमा राज, अभिराज, विजय राज, परमेन्द्र एवं गणमान्य अतिथि

जन्मदिवस के अवसर पर चांदी का मुकुट पहनाकर डॉ0 उदित राज को शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति

जन्मदिवस समारोह के अवसर पर बाएं से देशवाल, परमेन्द्र, नरेन्द्र सैनी, राजेन्द्र, सतपाल, प्रदीप मारवाह, डॉ0 उदित राज, श्रीमती सीमा राज, नीलम मारवाह, मानिकचंद झा, अनिल झा, ऋषि, राम आसरे पासवान, शनि जाटव, श्रीनिवास शर्मा, विक्रम सिंह व अन्य

दशकों से अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ एवं सामाजिक-राजनैतिक लोगों द्वारा डॉ0 उदित राज जी का जन्मदिवस 'जस्टिस डे' के रूप में मनाया जाता रहा है। आज का यह कार्यक्रम भी उसी कड़ी का एक हिस्सा था। इस कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य भूमिका भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा (दिल्ली इकाई) के महासचिव एवं डॉ0 उदित राज के सेक्रेटरी परमेंद्र की रही। उनका सहयोग नरेन्द्र सैनी, माला राम, धर्म सिंह, मानिक चंद, अनिल झा, निश्चल जैन, संजय जाटव, राजेन्द्र, रबीन्द्र, कपीस मित्तल, श्रीनिवास शर्मा, राम आश्रय पासवान, विक्रम, सतपाल, नरेश यादव, प्रवीन अग्रवाल, प्रदीप मारवाह, नीलम मारवाह, जितेन्द्र राणा एवं बाबूलाल आदि लोगों द्वारा किया गया। डॉ0 उदित राज ने आयोजकों को इस तरह का भव्य कार्यक्रम आयोजित करने पर धन्यवाद दिया।

डॉ0 उदित राज जी ने इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा जन्मदिन 'जस्टिस डे' के रूप में मनाया जाता रहा है। जिसमें देश में अमन-चैन, जातिविहीन समतामूलक समाज बनाने का संदेश गया। उन्होंने आगे कहा कि देश की उन्नति में सभी व्यक्तियों का योगदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं हर वक्त क्षेत्र की चिंता करता हूं। किसी भी समस्या को लेकर कोई भी आदमी हमसे सीधे सम्पर्क कर सकता है। मुख्य रूप से इस देश के दबे-कुचले, गरीब, किसान, मजदूर की हमेशा से मुझे चिंता रही है। आगे भी हम मूल समस्या को लेकर लड़ाई लड़ते रहेंगें।

+++

अजा/जजा परिसंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में देश में 80 प्रतिशत जिला इकाइयों के गठन का संकल्प लिया गया

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2016.

आज डॉ0 उदित राज के नेतृत्व में अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की ओर से एन.डी.एम.सी. कन्वेंशन सेंटर, जंतर-मंतर के सामने, नई दिल्ली पर एक दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में परिसंघ के पूरे देश के पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्त्ता एवं शुभचिंतक शामिल हुए और दलित आंदोलन की दिशा व दशा पर गंभीर चर्चा हुई। अधिवेशन में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि शीघ्र ही देश के 80 प्रतिशत जिलों में अजा/जजा परिसंघ की इकाइयां गठित करके विशेष सदस्यता अभियान चलाया जाएगा।

डॉ0 उदित राज जी ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने गत् 15 जनवरी को वित्तमंत्री, अरूण जेटली से मुलाकात करके एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से शिड्यूल्ट कास्ट स्पेशल कांपोनेंट प्लान एवं

(शेष पृष्ठ 5 पर)

रिसर्च –

ब्राह्मणों के 99 प्रतिशत डीएनए यहूदियों से मिलते है

यूरोपियन लोगो को हजारों सालों से भारत के लोगो में बहुत ज्यादा interest है। क्योंकि यहाँ अनेक व्यवस्थाएं हैं– धर्मव्यवस्था है, वर्णव्यवस्था है, जातिव्यवस्था है, अस्पृश्यता है, रीति रिवाज हैं, जिसने हजारों सालों से विदेशियों की जिज्ञासा को जगाया कि यह जो खास विशेषता है, भारत के लोगों की जिसका मिलन कहीं दुनिया में नहीं होता।

इसीलिए वैज्ञानिकों को हमेशा यह जिज्ञासा रही कि इस विशेषता का ''मूल'' कारण क्या है। मुश्किल हालात होने के बावजूद भी उसे हमेशा प्रेरित किया। इस वजह से इनके माध्यम से शोध हो रहा है।

अमेरिका के उताह विश्वविद्यालय (Washington) में माइकल बामशाद जो Biotechnology Dept. का HOD हैं। इसने ये प्रोजेक्ट तैयार किया था। उसे अगर लागू कर दिया जाए कैसे? क्योंकि भारत के लोग इस conclusion को मान्यता देने से इनकार कर देंगे। इसीलिये उसने एक और रास्ता निकाला। भारत के वैज्ञानिकों को involve करके उसे transparent method से प्रोजेक्ट तैयार किया जाये। इसीलिए मद्रास विशाखापट्टनम का Biotec-Dept. भारत सरकार का मानववंश शास्त्र – anthropology के लोग मिलकर प्रोजेक्ट में शामिल किया जो joint प्रोजेक्ट था। उन्होंने research किया। सारी दुनिया के sample के आधार पर उन्होंने ब्राम्हणों का DNA compare (सारे जाति धर्म के लोगों के साथ) किया गया।

यूरेशिया प्रांत में मोरुवा समूह है रशिया के पास काला सागर नमक area में ,अस्किमोझी भौगोलिक क्षेत्र में,'' मोरु नाम का DNA भारत के ब्राम्हणों के साथ मिला। इसीलिए ब्राम्हण भारत के नहीं है.'' महिलाओं में mitochondrial DNA(जो हजारों सालो बाद भी सिर्फ महिला से महिला ही ट्रान्सफर होता है) के आधार पर compare किया गया। विदेशी महिलाओं के साथ का DNA भारत की SC/ST/OBC की महिलाओं के साथ नहीं मिला। बल्कि ब्राम्हण के घरों में जो महिलाएं हैं। उनका DNA SC/ST/OBC कह महिलाओं के साथ मिला। आर्यन, वैदिक ये theory हुआ करती थी। अब तो इसका 100% वैज्ञानिक प्रमाण ही मिल गया है।

सारी दुनिया के साथ साथ भारत के भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मान्यता दी है।

<u>क्यों कि यह प्रमाणित हो गया है। DNA कितना मिला किसका यूरेशियन के साथ –</u>

1)ब्राम्हण =99.90%

2) क्षत्रिय=99.88%

3)वैश्य=99.86% .

राजन दीक्षित नाम का ब्राम्हण (Oxford में प्रोफेसर है) ने किताब लिखी। उनके चाचा जोशी हैं पूना में उन्होंने वो किताब publish की India में। ''ब्राम्हण का DNA और रशिया के पास काला सागर में, मोरुआ लोगों का और यहूदी (ज्यूज=हिटलर ने जिनको मारा था)

लोगो का DNA एक ही है । ऐसा क्यों किया उसने क्यों की अमेरिकन लोग भारत के लोगो को अमेरिका में asian न कहें!! राजन दीक्षित ने बामशाद के ही संशोधन को आधार बनाकर exactly वो प्रांत, आप जो यूरेशिया कह रहे हो ये कहाँ है, वो भी बताया। (राजन दीक्षित=एक महान संशोधक। ये आदमी सही मायने में भारतरत्न का हक़दार है)।

<u>DNA</u> <u>टेस्ट की जरुरत क्यों पड़ी ?</u>

संस्कृत और यूरोपियन language में हजारों शब्द एक जैसे मिले हैं। फिर भी ब्राम्हणों ने नहीं माना। फिर ये बात पुरातत्व विभाग ने सिद्ध की, मानववंश शास्त्र विभाग ने सिद्ध की, भाषाशास्त्र विभाग ने सिद्ध की फिर भी ब्राम्हणों ने नहीं माना जो की सच था। वो खुद भी जानते थे कि ब्राम्हण भ्रांतिया पैदा करने में बहुत माहिर लोग है । इस महारथ में पूरी दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसीलिए DNA के आधार पर संशोधन हुआ। ब्राम्हणों का DNA प्रमाणित होने के बाद उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग अब इस बात का विरोध करते हैं तो दुनिया की नजर में हम लोग बेवकूफ साबित हो जायेंगे। दोनों तथ्यों पर चर्चा होने वाली थी इसीलिए उन्होंने चुप रहने का निर्णय लिया। "ब्राम्हण जब ज्यादा बोलता है तो खतरा है। ब्राम्हण जब मीठा बोलता है तो खतरा नजदीक में पहुँच गया है और जब ब्राम्हण बिलकुल ही नहीं बोलता एकदम चुप हो जाता है तो भी खतरा है। Its a conspiracy of silence - Dr. B. R. Ambedkar । अगर वो कुछ छुपा रहे हैं तो हमें जोर से बोल देना चाहिए। इसका DNA टेस्ट का परिणाम क्या हुआ? अब हमें सारा का सारा इतिहास नए सिरे से लिखना होगा। जो भी लिखा है अनुमान प्रमाण पर। अब DNA को आधार बनाकर आप विश्लेषण कर सकते हो। जो ऐसा नहीं करेगा उसे लोग backward historian कहेंगे।

DNA ट्रान्सफर होता है पीढ़ी से पीढ़ी without change ।

आक्रमणकारी लोग हमेशा अल्पसंख्याक होते है और वहां की प्रजा बहुसंख्यांक होती है और जब आपस में वो आते हैं। तो हमेशा अल्पसंख्यक लोगों के मन में बहुसंख्यक लोगों के प्रति inferiority complex develop होता है । जनसंख्या के घनत्व की psychology होती है। इसीलिए उस समय ब्राम्हणों के मन में हीन भावना पैदा हो गया होगा। अपनी हीन भावना को इन पराजित लोगों में ट्रान्सफर करने के लिए उन्होंने योजना बनायीं।

युद्ध में पराजित किये हुये लोगों को गुलाम बनाना एक बात है और गुलाम बनाये हुये लोगों को हमेशा के लिए गुलाम बनाये रखना ये दूसरी बात है। ये समस्या ब्राम्हणों के सामने थी।

ऋग्वेद में ब्राम्हणों को देव कहा जाता था (देवासुर संग्राम = देव + असुर) मूलनिवासियों को दैत्य, दानव, राक्षस, शुद्र, असुर कहते थे। ये evidence है। अब देव ब्राम्हण कैसे हो गए? दीर्घकाल तक लोगों को गुलाम बनाये रखने के लिए उनको व्यवस्था बनानी पड़ीं। इसीलिए उन्होंने वर्णव्यवस्था बनायी। दैत्य, दानवों का नाम परिवर्तन करके उनको शूद्र घोषित किया। क्रमिक असमानता है तो ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य को अधिकार है तो शुद्र को भी अधिकार होना चाहिए। मगर वो अधिकार वंचित है। ऐसा क्यों किया? खुद को ब्राम्हण घोषित करने के लिए ।

ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य अगर एक ही है तो उन्होंने अपने को 3 हिस्सों में क्यों बांटा? हमको शूद्र घोषित, यानि गुलाम बनाने के लिए व्यवस्था बनाना जरुरी था। संस्कृतभाषा में वर्ण का अर्थ होता है रंग। इसका मतलब है की ये रंगव्यवस्था है (वर्णव्यवस्था)। संस्कृत डिक्शनरी में भी आपको ये मिलेगा। ये वर्णव्यवस्था/ रंगव्यवस्था क्यों है? क्यों कि ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य ये एक ही रंग के लोग हैं। इसीलिए रंगव्यवस्था में ये अधिकार संपन्न हैं।

चौथे रंग का आदमी उस रंग का नहीं है अर्थात् इसलिए अधिकार वंचित हैं। DNA की वजह से ये विश्लेषण करना संभव हैं Racial Discrimination Ideology है ब्राम्हणवाद। वर्णव्यवस्था बनाने से गुलाम बनाना और दीर्घकाल तक गुलाम बनाये रखना ब्राम्हणों को संभव हुआ।

ब्राम्हणों ने सभी धर्मशास्त्रों में सभी महिलाओं को शूद्र घोषित क्यों किया? ये आजतक का सबसे मुश्किल सवाल था। ब्राम्हण की माँ, बेटी, बहन, बीवी को भी उन्होंने शूद्र घोषित किया। DNA में "mitochondrial DNA" के आधार पर ये सिद्ध हुआ कि ब्राम्हणों के महिला और एससी एसटी और ओबीसी महिला का DNA मिलता है। वो जानते थे की जब उन्होंने प्रजनन के लिए यहीं की महिलाओं का उपयोग किया है। इसीलिए उन्हें शुद्र वर्ण में ढकेल दिया।

इसीलिए ब्राम्हण हमेशा purity की बात करता है। आदमी का DNA आदमी में ट्रान्सफर होता है। ये बात वो जानते थे इसीलिए औरत को तो वो हमेशा पाप योनि मानता आया है। क्योंकि वह उनकी कभी नहीं थी। DNA और धर्मशास्त्र दोनों के आधार पर ये सिद्ध कर सकते हैं। इससे ये भी सिद्ध हुआ कि आर्य ब्राम्हण स्थनांतरित नहीं हुये थे। वे आक्रमण करने के लिए ही यहाँ आये थे। क्योंकि जो आक्रमण करने के लिए आते हैं, उनके साथ महिलाएं बिलकुल भी वे नहीं लातें हैं। । ऐसी उस समय दृढ़ मान्यता भी थी। इसीलिए उनका आक्रमणकारी स्वभाव आजतक बना हुआ है।

<u>''बुद्ध ने वर्णव्यवस्था को समाप्त किया.''</u>

ओबीसी / एससी / एसटी के गुलामी के विरोध में लड़ने वाला वो सबसे बड़ा पुरखा है। इसका मतलब है वर्णव्यवस्था बुद्धपूर्वकाल में विद्यमान थी। ये evidence है। इस जनआंदोलन में बुद्ध को मूलनिवासियों ने ही सबसे ज्यादा जनसमर्थन दिया। तो जैसे ही वर्णव्यवस्था ध्वस्त हुई और चतुर्युत्री पर आधारित नई समाज रचना का निर्माण हुआ। उसमे समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाजव्यवस्था निर्माण की गयी। इसका मतलब है की बुद्ध गुलामी के विरोध में लड़ रहे थे।

इनकी इस क्रांति के बाद ही प्रतिक्रांति हुई जो पुष्यमित्र शुंग (राम) ने बृहद्रथ की हत्या करके की। वाल्मीकि शुंग के दरबार में राजकवि था और उसे सामने रखकर ही रामायण लिखी गयी। इसका evidence रामायण में खुद है। हत्या पाटलिपुत्र में हुई थी। शुंग की राजधानी अयोध्या है और रामायण में राम की राजधानी भी अयोध्या है। archeological evidence है। कोई भी राजा अपनी राजधानी का निर्माण करता है तो वह उसे युद्ध करके जीतता है, फिर अपनी राजधानी खड़ीं करता है। मगर अयोध्या युद्ध जीतकर खड़ीं की गयी राजधानी नहीं थी। इसीलिए उसका नाम रक्खा अयोध्या (अ+योध्या)। युद्ध ना होकर निर्माण की गयी राजधानी। शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया। रामायण में राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया।

ये जो प्रतिक्रांति शुंग ने की इसके बाद जातिव्यवस्था का निर्माण हुआ। पहले गुलाम बनाने के लिए वर्णव्यवस्था और क्रांति के बाद जब प्रतिक्रांति हुई उसके बाद जातिव्यवस्था का निर्माण हुआ। फिर उन्होंने योजना बनायी कि हमेशा के लिए अब बहुजनों का प्रतिकार ख़त्म कर दिया जाए। बिलकुल भी लायक ना रक्खा जाए। इसीलिए उन्होंने बहुजनों को 6000 अलग अलग जातियों के टुकड़ो में बाटां। इससे इन लोगो की एक psychology तैयार हो गयी कि हम प्रतिकार करने लायक नहीं है। गुलामो की ही ऐसी प्रतिक्रिया होती है। ये सबूत है गुलामी का। दुनिया में जाति व्यवस्था नहीं है इसीलिए दुनिया में कुटुंब व्यवस्था नहीं है। बुढ़ो के लिए old age home है foreign में।

जाति व्यवस्था को फिर से क्रमिक असमानता पर खड़ा किया ब्राम्हणों ने। अ–समान लोग आपस में समान होने चाहिए ये मगर क्रमिक असमानता में अ–समान लोग भी आपस में समान नहीं हैं। प्रतिकार अंदर ही अंदर होता है। जिसने गुलामी लादी उसके बारे में प्रतिकार करने का खयाल ही नहीं आता। ब्राम्हणों ने जातिअंतर्गत लड़ाई शुरू करवा दी। ये DNA सिद्ध करता है कि निर्माणकर्ता ब्राम्हण है। उसने सभी को विभाजित किया लेकिन खुद को कभी भी विभाजित नहीं होने दिया।

जाति को बनाये रखने के साथ ब्राम्हणों की supremacy जुड़ी हुई है। इसीलिए उनके सामने ये हमेशा संकट खड़ा रहा कि कैसे इस जातिव्यवस्था को बनाये रक्खा जाये। Evidence= कन्यादान system = ये कोई वस्तु नहीं है दान करने के लिए। धार्मिक व्यवस्था इसके लिए ऐसी बनायीं गयी। स्त्री की अगर उमर हो

(शेष पृष्ठ 3 पर)

(पृष्ठ 2 का शेष)

ब्राह्मणों के 99 प्रतिशत डीएनए यहूदियों . . . .

गयी, शादी योग्य हो गयी तो उसकी शादी करने के की जिम्मेदारी माँ–बाप की ही होगी। Bramhanical Social Order- परिवार ही शादी करेगा। अगर कन्या खुद अपनी पसंद से शादी करेगी तो जाति के बाहर जाकर शादी कर सकती है। तो जातिव्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। ब्राम्हण की supremacy ख़त्म जो जाएगी। तो बहुजनों की गुलामी ख़त्म हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए कन्यादान system निकाला।

बालविवाह

कन्या के विवाह योग्य होने के पहले ही शादी कर दी जाये। क्यों कि विवाह योग्य होगी तो अपनी पसंद से शादी कर सकती है। इसीलिए बचपन में ही उसकी व्यवस्था कर दी। माँ–बाप जाति के अंतर्गत ही शादी करेंगे। For more information read Caste in India & Inhalation of Caste - Dr.B.R Ambedkar -

विधवा विवाह

विधवा विवाह पर पाबंदी क्यों थी ? अगर किसी विधवा से कोई शादी योग्य लड़का समाज के अंदर का उससे हुई। तो समाज में उसके लिए एक लड़के की कमी होगी। वो लड़की जाति के बाहर जाकर शादी कर सकती है। तो भी जाति व्यवस्था खतरे में पड़ेगी। जाति के अंतर्गत विवाह जाति बनाये रखने का सूत्र है।

जातिव्यवस्था बनाये रखने के लिए उन्होंने महिलाओं का इस्तेमाल किया।

मतलब विधवा को शादी न करने का बंधन। विधवा विवाह पर पाबंदी थी। लेकिन उन्होंने देखा की ये इसे टिकाये रखना ज्यादती है। ये सम्भव नहीं है। तो ये विधवा सुंदर नहीं दिखनी चाहिए। तो उसके बाल काट दिए गए। ताकि कोई उसकी तरफ आकर्षित ना हो और कोई उसके साथ शादी करने के लिए तैयार न हो जाये। यानि किसी भी स्थिति में ये जाति व्यवस्था में बने ही रहनी चाहिए।

सती प्रथा

दूसरा रास्ता ब्राम्हणों ने निकाला। अपने पति के साथ मरनेवाली जो स्त्री है ये पतिव्रता स्त्री है। ये सचचरित्र स्त्री है। इसीलिए ये सती है। ब्राम्हणों ने ये जो गलत और घटिया काम किया। इस गलत और घटिया काम का उन्होंने गौरव किया। सच के लिए जान दे रही है। गौरवभाव निर्माण किया। जो जीवंत रही है वो अपने पति की चिता पर जिन्दा जलनी चाहिए। इसके लिए स्त्री में प्रेरणा पैदा की जाये। ये प्रेरणा पैदा करने के लिए उन्होंने औरतों के लिए खास त्यौहार बनाया। जिसका नाम था वडसावित्री।

वडसावित्री

(प्रेरणा) संस्कार बनाया योजनाबद्ध तरीके से। औरत धागा लेकर चक्कर काटती है और कहती है यही पति मुझे सातों जनम तक मिलना चाहिए। ये शराबी हैं फिर भी मिलना चाहिए। मारता–पीटता है, फिर भी मिलना चाहिए। यह गहरी बात है। ये बार–बार हर साल त्यौहार आता है। तो हर साल उनके मन में ये संस्कार

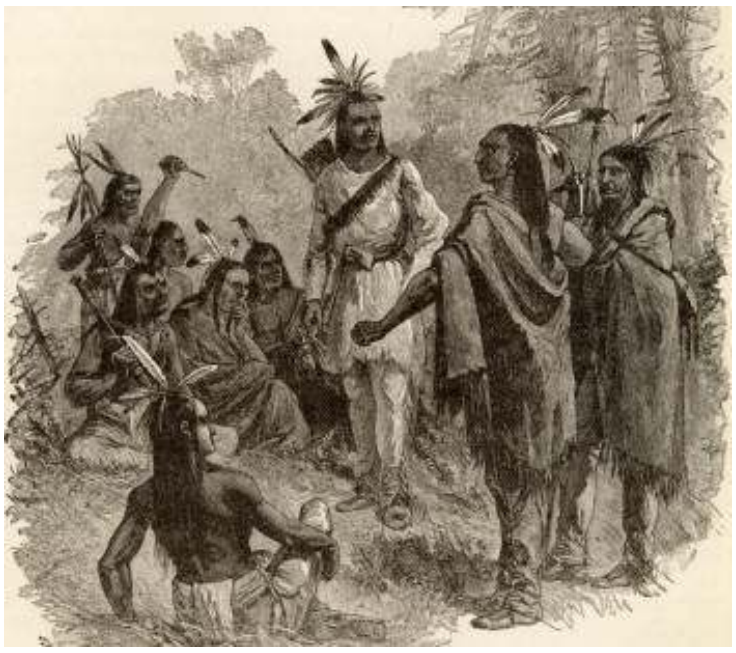

किया जाता है। यही पति तुमको मिलने वाला है और कोई पति मिलने वाला नहीं है। अगर तुम जिन्दा रहती हो तो जब तक जिंदा रहोगी तब तक तुम्हारा पुनर्मिलन होने के लिए तुम देर कर दोगी। क्योंकि अगर तुम अपने पति की चिता पर मर जाओगी। तो एक ही तारीख को, एकही समय को पैदा हो जाओगी, पुनर्जन्म हो जायेगा। फिर दोनों का मिलन भी हो जायेगा। अगर एकसाथ जाओगी। जिन्होंने षड्यंत्र किया, जिन्होंने योजना बनायीं, कोई चोर में चोर हूँ ये नहीं बताता। ऐसा ही ब्राम्हणों के बारे में है। जनम–जनम की theory महिलाओं में प्रेरणा देने के लिए की गयी। परंतु अब यह प्रथा समाप्ति पर है।

क्रमिक असमानता

जातिव्यवस्था बंधन डालने के बाद ही निर्माण करना /maintain करना संभव है। गुलाम बनाने के लिए। हर कोई किसी न किसी के ऊपर होने से वो समाधानी रहता है। ये सारे लोग अपने आप में लड़ते रहे। इसीलिए ब्राम्हणों के लिए वो unite हो ही नहीं सकते। consolation prize is not a real prize- यहीं पर लगना चाहिए। ये ऊंचनीच की भावना एक आदमी को नहीं पूरे humanity को ख़तम करती है.

अस्पृश्यता

ये बुद्ध पूर्व काल में नहीं थी। जातिव्यवस्था बुद्ध पूर्व काल में नहीं थी। इसीलिए literature में नहीं है। इसीलिए भ्रांति होती है। जिन बुद्धिष्ट लोगों ने ब्राम्हणी धर्म से compromises किया। उसे अपना लिया। वो आज OBC है। उनपर ब्राम्हणवाद का प्रभाव है। OBC, untouchable, tribe भी प्रतिक्रांति के बाद के वर्ग है।

सिंधु घाटी की सभ्यता पैदा करने वाले भारतीय लोगों से इतनी बड़ी महान सभ्यता कैसे नष्ट हुई, जो 4500, 5000 पूर्व थी। ये अंग्रेजो ने पूछा था। एक अंग्रेज़ अफसर को इस का शोध करने के लिए भी बोला गया था। बाद में इसके शोध को राघवन और एक संशोधक ने continue किया। पत्थर और ईटें के टेस्ट में पता चला कि ये संस्कृति अपने आप नहीं गिरी वो गिराई गयी। दक्षिण राज्य केरल में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के 429 अवशेष मिले। ब्राम्हण भारत में ईसा पूर्व 1600, 1500 शताब्दी पूर्व आया।

ऋग्वेद में इंद्र के संदर्भ में 250 श्लोक आतें हैं। सबसे अधिक श्लोक इंद्र पर है। जो ब्राम्हणों का नायक है। बार–बार ये श्लोक आता है। 'हे इंद्र उन असुरों के दुर्ग को गिराओ' उन असुरों(बहुजनों) की सभ्यता को नष्ट करो। ये धर्मशास्त्र नहीं बल्कि criminal दस्तावेज हैं।

भाषा–शास्त्र के आधार पर ग्रिअरसन ने भी ये सिद्ध किया की अलग–अलग राज्यों में जो भाषा बोली जाती हैं, वो सारी origin from पाली है।

DNA का evidence निर्विवाद और निर्णायक है। क्योंकि वो तर्क, दलील पर खड़ा नहीं है। जिसे lab में जाकर प्रमाणित किया जा सकता है। lab कोई जाती नहीं है science है- lab धर्मनिरपेक्ष है।. इसीलिए संइस निर्णायक और निर्विवाद है। कोई भी आदमी अपना DNA टेस्ट संइस में जाकर करा सकता है। इस DNA के शोध में पूरी दुनिया से शोध करने वाले 265 लोग थे। ''बामशाद का ये शोध 21 May 2001 को 'nature' नाम के अंक में, जो दुनिया का वैज्ञानिक सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त अंक है उसमे आया था।

बाबासाहब अंबेडकर की उम्र सिर्फ 22 साल थी जब उन्होंने विश्व की जाति का origin क्या है ? इसकी खोज किया था और 2001 में जो DNA research हुआ था। बाबासाहब का और माइकल बामशाद का मत एक ही निकला था।

ब्राम्हण सारी दुनिया के सामने पूरे expose हो चुके थे। फिर भी मापदंड के आधार पर ये जो दक्षिण राज्य के ब्राम्हणों ने दो विभिन्न नस्लों की संतान हैं। दो पूर्वज समूह की संतान है, भारतीय ऐसा झूठा प्रचारित करने के लिये, अपना विदेशीगण छिपाने के लिए, उन्होंने हमेशा की तरह ब्राम्हण theory use करते हुये, पूर्व के DNA संशोधन को ख़ारिज नहीं किया और एक झूठ media के द्वारा प्रचारित करना शुरू कर दिया कि अभी कोई भी मूलनिवासी कह नहीं सकता है। सब अब संमिश्र है। उन्होंने कहां का मापदंड ढूंडा ? उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो आदिवासी जनजाति हैं। उसकी दलील देकर कहा कि ये अफ्रीकन का वंशज है। वो इधर से आया था और इधर से यूरोपियन countries में चला गया। तो कैसे गया ? इसका शोध करना चाहिए। ऐसा कहा माइकल बामशाद के विज्ञान द्वारा किये गए शोध को नकारने के लिए । उन्होंने विज्ञान का सिर्फ नाम लिया। सिर्फ उस प्रचार में विज्ञान शब्द डाला। उससे झूठ प्रचारित किया। ब्राम्हण अगर तुमको यही झूठी कहानी बताये तो पूछो कि इन दो में से कौन सा विदेश से आया ? विदेशी का DNA बताओ ? लेकिन वो ये साबित कर ही नहीं सकते।

ब्राम्हण मुसलमान विरोधी घृणा अभियान क्यों चलाते हैं ? क्यों कि ब्राम्हणवाद और बुद्धिज्म के टकराव में जो ब्राम्हण विरोधी बुद्धिष्ट मुसलमान बने। उन्होंने ब्राम्हण धर्म को नहीं अपनाया। इसीलिए ये सब पहले से किया जा रहा है। क्योंकि ब्राम्हण जानता है कि ये मूल के बुद्धिष्ट लोग हैं।

अंग्रेजो के गुलाम ब्राम्हण थे और उनके गुलाम मूलनिवासी बहुजन थे। जो आज तक आजाद नहीं हुये हैं। आजादी की जंग में जो आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे उनके सामने ये समस्या थी। इसीलिए बाबासाहब ने अंग्रेजो को कहा था कि ब्राम्हण को आजाद करने के पहले हम बहुजनों को आजाद जरुर कर दें। अगर तुमने ब्राम्हणों को हमसे पहले आजाद कर दिया। तो ब्राम्हण हमको आज़ाद करने वाले नहीं हैं। ये आशंका सिर्फ बाबा साहब के मन में ही नहीं थी बल्कि मुसलमानों के भी मन में थी। ये बात जिन्ना के संज्ञान में थी इसीलिए 14 Aug. 1947 को पाकिस्तान बना। मुसलमानों ने अंग्रेजो को कहा कि गांधी के पहले एक दिन हमको आज़ादी दे देना और हमारे बाद गाँधी को देना। अगर तुमने गाँधी को पहले दे दिया तो गाँधी बनिया है हमको कुछ नहीं देगा। ब्राम्हणों ने अपनी आजादी की लड़ाई हमको सीढ़ी बनाकर लड़ी और वे अंग्रेजो को भगाकर आज़ाद हो गए।

DNA संशोधन आया

उसने सिद्ध किया कि ब्राम्हण यहाँ के नहीं है। ब्राम्हण विदेशी हैं। जब ये देश इनका कभी था ही नहीं, उन्होंने कभी ये माना नहीं। इसीलिए तो ब्राम्हण हमेशा हमको राष्ट्रवाद की theory बताता आया है कि हम कितने राष्ट्रभक्त हैं और मूल बात छुपाता है, इसका मतलब एक विदेशी देश छोड़कर गया। दूसरा विदेशी देश का मालिक हो गया। DNA ने ये सिद्ध कर दिया। दूसरे विदेशी यानि ब्राम्हणों ने ये propaganda किया कि भारत आज़ाद हो गया । भारत आज़ाद नहीं हुआ । ब्राम्हण आज़ाद हुआ। अर्थात विदेशियों का राज हैं। बहुजनों को आज़ादी हासिल करने का कार्यक्रम भविष्य में चलाना ही पड़ेगा। ये मामला अभी समाप्त नहीं हुआ। इतने conclusion draw होते हैं DNA के आधार पर ये दुनिया के 600 cr. में से 100 cr. जिनकी प्रजा है। उन 100 cr. को प्रभावित करने वाला संशोधन है। कल्पना करो कितना मूलभूत और कितना महत्वपूर्ण संशोधन।

– नवभारत टाइम्स से
लिया गया लेख

http://www.kohraam.com/my-opinion/99-percent-dna-of-brahman-match-from-jews-3992.html

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष : 600 रुपए
एक वर्ष : 150 रुपए

मुख्यमंत्री केजरीवाल डॉ. अम्बेडकर विरोधी, बंगला खाली करके परिनिर्वाणभूमि को दो

वाह जी, केजरीवाल क्या आपको पता नहीं कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के महान योगदान से समूचा राष्ट्र गौरावान्वित है। डॉ0 अम्बेडकर की राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रहित, राष्ट्र के नवनिर्माण और उनके द्वारा रचित संविधान से अभीभूत होकर उनकी 125वीं जयंती पर देश की सरकार ने देश की संसद ने और सभी राजनैतिक दलों ने उन्हें श्रद्धपूर्वक स्मरण और नमन किया है। दिल्ली सरकार की सत्ता में बैठकर आपने वह कर दिया, जिसकी कल्पना देशवासियों को नहीं थी। क्या सत्ता के निशाने ने आपको इंसान होने की व्यवहारिकता से भी दूर कर दिया है।

मामला संविधान निर्माता, राष्ट्र नेता और दलितों के मसीहा डॉ. बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर के सम्मान से जुड़ा है। दिल्ली के जिस बंगले-कोठी को लम्बे समय से भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, डॉ0 अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक परिनिर्वाण भूमि के लिये मांग रहा था, जिसके लिये केन्द्र सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को अनेक बार पत्र लिखे प्रस्ताव भेजे थे, आपने उस बंगले को डॉ0 अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक के लिए नहीं दिया। इसके उलट आपने उस बंगले को मुख्यमंत्री निवास बना दिया है और उसमें आकर खुद रहने लगे। दिल्ली विधान सभा के सामने अलीपुर रोड पर 26 नम्बर की कोठी डॉ. अम्बेडकर की परिनिर्वाण भूमि (निधन स्थली) का राष्ट्रीय स्मारक है।

इसके बिल्कुल पास ही चालीस फिट चौड़ी सड़क पर फ्लेग काटन रोड में अब मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल का निवास बन गया। इसके सामने सड़क पर पिछले दस वर्षों से हर 6 दिसंबर को डॉ0 अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय सम्मान सभा एवं श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित होता है। कार्यक्रम करने की अनुमति पिछले दस वर्षों से लोक निर्माण विभाग का कार्यालय देता आ रहा है चूंकि देश भर के कोने कोने से हजारों की संख्या में कार्यकर्त्ता इस कार्यक्रम में पहुंचकर श्रद्धासुमन एवं सम्मान प्रकट करते हैं। दिल्ली पुलिस एवं संबंधित थाने का भी इसमें अच्छा सहयोग मिलता है। लेकिन इस वर्ष मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हद पार करके इस कार्यक्रम को ही रोकने की कोशिश की। उनके अधिकारी इसी काम में लगे रहे।

पिछले दस वर्षों से यहां पर लगातार सम्मान सभा का कार्यक्रम होता है। इस वर्ष सड़क पर कार्यक्रम करने की अनुमति आयोजककर्त्ता समिति ने प्राप्त की थी। बावजूद इसके केजरीवाल ने लोक निर्माण विभाग और पुलिस एवं थाने के अधिकारियों को अपने निवास पर बुलाकर बिठाये रखा, उनके ओ.एस.डी और अधिकारियों द्वारा डांटा-फटकारा गया

और रात भर डॉ. अम्बेडकर सम्मान सभा का स्टेज, टेन्ट और कुर्सियां यहां पर नहीं लगने दिया। कार्यक्रम के दिन सुबह आठ बजे जब देश भर की जनता, कार्यक्रम स्थल पर पहुचंने लगी तब दिल्ली पुलिस की एक समझदार एसीपी ने विवाद में हस्तक्षेप करके यहां स्टेज, टेंट और कुर्सियां थोड़ी कम संख्या में लगाने दिया। जो कार्यकर्त्ता अनेक राज्यों से आए थे वे लोग रैली के रूप में यहां पहुचंने के लिए निकले थे, उन्हें रास्तें ही पुलिस ने रोक दिया। बहरहाल यहां सम्मान सभा प्रातः 11 बजे से प्रांरभ होकर शाम 5 बजे तक शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न हुई। श्री केजरीवाल आपने निवास पर थे। कार्यक्रम स्थल से और इस परिनिर्वाणभूमि समारक से 20 फिट की दूरी पर थे जबकि आयोजन समिति ने उन्हें पत्र देकर आमंत्रित किया था। श्रीमान केजरीवाल आप पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, जिस जनता ने आपको कुर्सी सौंपी है, वह जनता आपके कुर्सी से उतार भी सकती है। दिल्ली के एस.सी., एस.टी. के दलित लोगों ने भी आप पर विश्वास करके सत्ता में बिठाने के लिए वोट दिया है। उसके बदले आपने डॉ. अम्बेडकर और दलितों के प्रति असम्मान का यह सिला दिया है। आपका आचरण बताता है कि आप डॉ0 अम्बेडकर विरोधी हैं।

असल में केजरीवाल की डॉ. अम्बेडकर एवं दलित विरोधी मानसिकता पर सवाल खड़ा हुआ है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सारा राष्ट्र और राज्यों द्वारा उनकी 125वीं जयंती पर जब डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर को सम्मान देने खड़े थे, तब मुख्यमंत्री केजरीवाल डॉ0 अम्बेडकर के सम्मान के विरोध में खड़े थे। लोग बताते हैं कि श्री केजरीवाल प्रारंभ से ही डॉ0 अम्बेडकर एंव दलितों को प्राप्त आरक्षण के विरोधी रहे हैं। केजरीवाल ने जेएनयू में एस.सी.एस.टी. के आरक्षण विरोधी मुहिम एवं आवाज में अग्रणी रहे हैं। अपनी पार्टी के मंच और चुनाव प्रचार के दौरान वे कहते थे कि मुख्यमंत्री बनने पर वे सरकारी बड़ा बंगला नहीं लेंगें, आम आदमी की तरह मकान में ही रहेगें। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने यह बड़ा सरकारी बंगला रहने के लिए ले लिया। वे कहते थे कि मुख्यमंत्री बनने पर पुलिस की सुरक्षा नहीं लेगें, आम आदमी की तरह ही रहेगें लेकि अब वे पुलिस सुरक्षा लेकर, पुलिस के घेरे में और पुलिस की पायलट गाड़ी के साथ काफिले में चलते हैं। 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर की सम्मान सभा के कार्यक्रम स्टेज को उनके बंगले के सामने से लगी सड़क पर इसलिये नहीं लगने दे रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सुरक्षा को वे खतरा मान रहे थे।

श्री केजरीवाल अब जिस कोठी में रहते हैं, उनके पहले इस कोठी में विधान सभा अध्यक्ष श्री चौधरी प्रेम सिंह रहते थे, उनके बाद विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री अम्बरीश गौतम रहते थे। वे 6 दिसंबर को डॉ0 अम्बेडकर की इस सम्मान सभा के कार्यक्रम में आगे होकर उपस्थिति रहते थे। इस वर्ष श्री केजरीवाल इस बंगले में रहने आ गए। कार्यक्रम के 15 दिन पहले ही उन्हें इस सम्मान सभा में प्रमुख अतिथि के रूप में आने हेतु निमंत्रण भेजा गया था। कार्यक्रम के दिन श्री केजरीवाल दो बार कार्यक्रम के मंच के पास से अपने काफिले के साथ बाहर निकले और कुछ देर के बाद बंगले में वापिस आए लेकिन उन्होंने सिर्फ पांच मिनट के लिए भी इस पावन भूमि पर श्रद्धासुमन अर्पित करने आने की जहमत नहीं उठायी।

दिल्ली में स्थित 26 अलीपुर रोड के इस बंगले में ही 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का निधन हुआ था। यहां उनके पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए रखा था। उसके बाद उन्हें मुंबई लेजाकर दादर (चैत्यभूमि) में उनकी अंत्येष्टि की गई थी।

राजस्थान के महाराजा सिरोही ने उन्हें यह बंगला रहने के लिए दिया था। उनके निधन के उपरांत इस बंगले को उद्योगपति जिंदल ने खरीद लिया था और इसका पुनर्निर्माण कर वे इसमें रहने लगे थे। देश में श्री वी.पी. सिंह की सरकार बनी तो उन्होंने डॉ0 अम्बेडकर को राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया और भारत सरकार ने डॉ0 अम्बेडकर प्रतिष्ठान की स्थापना की। देश के दलितों की मांग पर इस बंगले का अधिग्रहण कर इसे खरदीकर इसे डॉ0 अम्बेडकर स्मारक बनाने की मंजूरी श्री वी.पी. सिंह द्वारा दी गयी। उस समय के सामाजिक न्याय मंत्री श्री रामविलास पासवान के प्रयासों के बावजूद भी उद्योगपति जिंदल से सरकार यह बंगला नहीं खरीद पायी। जब केन्द्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एन.डी.ए. की सरकार बनी और डॉ0 सत्यनारायण जटिया सामाजिक न्यायमंत्री बने तब प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने कैबिनेट से 16 करोड़ रूपये मंजूर किये और उद्योगपति श्री जिंदल को यह राशि अदा करके वर्ष 2003 में भारत सकरार द्वारा इस बंगले को खरीदा गया। भारत सरकार ने इसे डॉ0 अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया और प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने यहां उपस्थित होकर अपने हाथों से समारोहपूर्वक इसे राष्ट्र को समर्पित-लोकार्पित किया था।

बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर ने इस बंगले में रहकर राष्ट्र की सेवा की, और राष्ट्र को कीर्तिमान दिलाया। यहां दिल्ली में उन्होंने भारत का संविधान लिखा और प्रसिद्ध ग्रंथ 'बुद्धा एंड हिज धम्मा'' लिखा। सदियों से उपेक्षा एवं अन्याय के शिकार दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं महिलाओं को सम्मान एवं बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए यहां रहकर उन्होंने निर्णायक लड़ाई लड़ी। नागपुर में हुई ऐतिहासिक बौद्ध धर्म की दीक्षा के निर्णय एवं तैयारी को उन्होंने यहां पर ही मूर्तरूप दिया। यहां से उन्होंने देश के दलितों-पिछड़ों की तकदीर एवं तस्वीर बदली थी। फिर यहां उन्होंने अंतिम सांस ली। यह पावन भूमि करोड़ो देशवासियों की आस्था, प्रेरणा, सम्मान, स्वाभिमान और शक्ति केन्द्र एक तीर्थस्थल है। इसलिये डॉ0 अम्बेउकर परिनिर्वाणभूमि सम्मान कार्यक्रम समिति का सभी दलों के नेताओं द्वारा मिलकर गठन किया गया और अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर दिल्ली में और देश भर में धरने, प्रदर्शन, आंदोलन शुरू किये गये। पहली मांग है कि यहां भव्य सुन्दर स्मारक बनाया जाए, जिसे भारत सरकार ने मंजूर कर लिया है। स्मारक का डिजाइन एवं इसकी लागत 110करोड. रूपये स्वीकृत हो चुके हैं। और शीघ्र ही स्मारक का निर्माण शुरू हो जाएगा। दूसरी मांग है, इसे गांधी समाधि राजघाट जैसा सम्मान का दर्जा संसद से कानून बनाकर दिया जाए। तीसरी मांग है, इस स्मरक के निकटतम आस-पास के सभी सरकारी एवं निजी बंगलों को सरकार अधिग्रहण करे और यहां बड़ा भूमि परिसर उपलब्ध कराये।

भारत सरकार का सामाजिक न्याय मंत्रालय इस परिनिर्वाण भूमि स्मारक के निकट के उस सरकारी बंगले को अब जिसमें केजरीवाल रहने आ गऐ हैं लेना चाहता है। पहले इस बंगले को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष का बंगला कहा जाता था। यह बंगला दिल्ली सरकार की सम्पत्ति होकर उसके आधिपत्य में है। पूर्व में तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री को प्रस्ताव के साथ पत्र लिखे हैं। वर्तमान में मोदी सरकार बनने पर पुनः सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिल्ली सरकार को इस बंगले के अधिग्रहण के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रस्ताव के साथ पत्र लिखे हैं। लेकिन दुख की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इसे निवास बनाकर यहां आकर रहने लगे हैं। जिसका सीधा मतलब है कि केजरीवाल इस बंगले को डॉ0 अम्बेडकर परिनिर्वाण भूमि स्मारक के लिए नहीं देना चाहते हैं। उनके इस अहंकार और करतूत से देश में केजरीवाल की डॉ. अम्बेउकर एवं दलित विरोधी छवि बन रही हे। उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फणनवीस से सीखना चाहिये, जिन्होंने अपनी सरकार की ओर से 35 करोड़ रूपये में लंदन में उस बंगले को खरीदकर स्मारक बना दिया, जहां रहकर डॉ. अम्बेउकर लंदन में पढ़ा करते थे। मुख्यमंत्री केजरीवाल को अपने इस बंगले को तत्काल खाली कर देना चाहिए और उदारता तथा बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए इस बंगले को डॉ. अम्बेडकर परिनिर्वाण भूमि स्मारक के लिए दिल्ली सरकार की ओर से शीघ्र देना चाहिए। क्योंकि जिस बंगले में अभी श्री केजरीवाल रह रहे है, इस बंगले को लेने के लिए पिछले दस वर्षों से देश में दलितों का आंदोलन चल रहा है। इसमें कोई राजनीति नहीं हैं यह दलितों की पुरानी मांग है। अगर श्री केजरीवाल इस बंगले को नहीं देते हैं तो निश्चित ही देश भर में उन्हें दलितों की नाराजगी एवं आक्रोश का सामना करना पड़ सकता हैं इस संवेदनशील मामले में उन्हें विचार करना चाहिए।

– इन्द्रेश गजभिये
राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ0
अम्बेडकर परिनिर्वाण भूमि समिति

24 जनवरी, 2016 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख

क्या यह मां का प्रेम है

17 जनवरी को हैदराबाद विश्वविद्यालय में बहुत ही दुखद घटना हुई। रोहित वेमुला ने एक पत्र छोड़कर आत्महत्या कर लिया यह कहते हुए कि उनकी जिंदगी खाली थी और बचपन से ही अकेला महसूस कर रहे थे। वे महज एक वस्तु बनकर रह गए हैं। पांच विद्यार्थियों में से एक यह थे, जिन्हें पहले विश्वविद्यालय से निकाला गया और बाद में परिवर्तित करके छात्रावास से बर्खास्त कर दिया गया। यह घटना पूरे देश में आग की तरह फैल गयी। तमाम संगठन श्री बंडारू दत्तात्रेय – श्रम मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री – श्रीमती स्मिृति ईरानी एवं विश्वविद्यालय पर प्रहार कर रहे हैं कि इनके पत्र ने इन विद्यार्थियों को देशद्रोही कहा था। मैं यहां पर कोई फैसला नहीं सुना रहा हूं और न ही किसी दोषी को बचा रहा हूं। इससे एक अवसर जरूर मिला कि जो लोग आंदोलित हैं, क्या वास्तव में उनका प्रेम मां का है या दाई का। क्या दाई का प्रेम मां में बदल सकता है?

यह दिनचर्या हो गयी है कि देश में तमाम स्कूलों में दलित बच्चे दोपहर का भोजन सवर्णों के साथ नहीं करते। छात्रावास में दलित–आदिवासी की एक अलग विंग होती है। छात्रवृत्ति नहीं मिलती और मिलती है तो देर से, जिससे परीक्षा से भी वंचित कर दिए जाते हैं। छात्रावास बुरी परिस्थिति में हैं। यह आम बात है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन में भेदभाव किया जाता है। भेदभाव को कम करने के लिए दलित प्रतियोगियों के लिए अलग से साक्षात्कार बोर्ड बनाया जाता है ताकि इनके साथ न्याय हो सके। लेकिन देखा यह जाता है कि औसत अंक सामान्य वर्ग वालों से कम होता है। प्रायः शोध कर रहे छात्रों के साथ भेदभाव होता है। यह कोई अपवाद नहीं है कि बड़े पैमाने पर पद खाली पड़े हैं। प्रोफेसर और उप कुलपति तो ढूढ़ने से नहीं मिलेगें। सरकार की आउटसोर्स की नीति वीआरएस, सीआरएस और ठेकेदारी प्रथा आदि से आरक्षण बहुत कमजोर हो गया है। लाखों पद अदालत के हस्तक्षेप से खाली पड़े हुए हैं। पदोन्नति में आरक्षण हटने से तमाम समस्याएं पैदा हो गयी हैं। उ0प्र0 में हजारों कर्मचारी और छात्र डिमोट हो गए हैं। यहां तक कि जो सामान्य योग्यता से आएं हैं, उनका भी डिमोशन किया गया है। अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ मेरे नेतृत्व में गत् कई वर्षों से इन अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है।

यदि राजनीति, सरकारी नौकरी और शिक्षा में मिले आरक्षण के लाभ को एक क्षण के लिए हटा दिया जाए तो दूर–दूर तक कहीं दलितों–आदिवासियों की भागीदारी किसी क्षेत्र में दिखती नहीं। अगर आरक्षण न होता तो आज भी ये आदिम युग का जीवन जीते। रोहित वेमुला परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आरक्षण की ही पैदाइश है। यदि आरक्षण न होता तो वह न तो विश्वविद्यालय पहुंच पाता और न ही छात्रावास और न हीं आत्महत्या करता। जो दलित–आदिवासी हजारों वर्षों में विकास न कर सके आरक्षण मिलने के बाद कुछ ही सालों में कर डाले। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण से कुछ ही लोगों का फायदा हुआ है लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अन्य क्षेत्र जैसे – मीडिया, उद्योग, व्यापार, बाजार, आयात–निर्यात, शेयर बाजार, कला एवं संस्कृति, उच्च न्यायपालिका एवं शिक्षा में क्या इनकी भागीदारी हो पायी है? जो भी आरक्षण के बिना विकास और सम्मान मिला है, वह भी इसी की वजह से ही संभव हुआ है। आरक्षण के पहले हजारों वर्षों तक क्यों नहीं इनकी भागीदारी किसी क्षेत्र में थी?

इस घटना पर विशेष रूप से वामपंथी ज्यादा हो हल्ला कर रहे हैं। क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि जब हम अपने सशक्तिकरण और भागीदारी के मूलस्रोत के लिए संघर्ष करते हैं तब ये वामपंथी कहां गायब हो जाते हैं। कुछ मामलों में कभी–कभार बयान जरूर आ जाता है, लेकिन असली संघर्ष दलित–आदिवासी ही करते हैं। वोट के दबाव के कारण पार्टियां भी कुछ मांगों को मानती हैं। जब रोहित और उसके साथी 15 दिनों तक हड़ताल कर रहे थे तब कहां थे ये लोग। सीपीएम के छात्र प्रकोष्ठ (एस. एफ.आई) ने इनका जमकर विरोध किया था। अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का गठन 1997 में इसलिए हुआ था कि पांच आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे। यह भी ध्यान देने की बात है कि जब केन्द्र में सामाजिक न्याय की सरकार थी तभी यह हुआ था। इसको निरस्त करने के लिए जब हमने संघर्ष शुरू किया तब ये तथाकथित प्रगतिशील और वामपंथी नजर नहीं आए। पूरे देश स्तर से लेकर रामलीला मैदान से जंतर–मंतर तक लड़ाई लड़ते रहे लेकिन जो हमारे अधिकार का स्रोत था, उनका समर्थन इनमें से किसी से नहीं मिला। वाजपेयी जी की सरकार ने इन आरक्षण विरोधी आदेशों को निरस्त किया। क्या जो आज आंदोलित हैं ये हमारी जिंदगी और मौत के अहम प्रश्न–आरक्षण के लिए धरना–प्रदर्शन इसी तरह से करते हैं? क्या ये सिद्ध कर सकते हैं कि इनकी वजह से दलितों, आदिवासियों का सशक्तिकरण हुआ है? अगर हुआ होता तो बंगाल, केरल, त्रिपुरा में भी व्यवसायी, राजनैतिक एवं सामाजिक नेतृत्व दलितों में से भी पैदा हुआ होता।

जब हमारी हत्या होती है या कोई जघन्य भेदभाव तो कभी–कभी मीडिया से लेकर वामपंथी और दक्षिणपंथी सभी आंदोलित हो जाते हैं। क्या यह वास्तव में मां का प्रेम है? जब हम अपने सम्मान एवं अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, तब अखबार में नहीं के बराबर छपता है या टेलीविजन चैनलों के लिए हम जैसे हैं ही नहीं। रोहित वेमुला 7 दिसंबर को अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ द्वारा की गयी रैली रामलीला मैदान, दिल्ली में शामिल थे, जिसका मकसद पदोन्नति एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण आदि था। वे जानते थे कि उनका उद्धार कैसे होगा? रामलीला मैदान भरा था लेकिन मीडिया में नहीं के बराबर छपा और दिखा और यह हमेशा से होता रहा है। आरक्षण से वंचित करने का मतलब कि करोड़ों रोहित वेमुला की हत्या है। जब तक अधिकार, सम्मान और भागीदारी न मिले तब तक हम एक जिंदा शरीर मात्र हैं। जो शक्तियां आज हमारी हमदर्द दिख रही हैं, क्या वे हमारे सशक्तिकरण के स्रोत को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं? कुछ दलित मेरी आलोचना कर रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाकर दलितों के सवालों पर नतमस्तक हो गया हूं तो उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि जो मेरी प्रतिबद्धता है, वह न तो कमजोर हुई है और न ही आगे कभी होगी। मुझे क्या करना है, यह मालूम है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे क्यों नहीं एक होकर संघर्ष करते? इनमें से ज्यादातर लोग सवर्णों के नेतृत्व में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। क्या दलित आपस में जातिवाद नहीं करते? जब तक इस समाज में जाति के आधार पर बंटवारा होता रहेगा, तब तक हम विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते।

– डॉ0 उदित राज

(पृष्ठ 1 का शेष)

अजा/जजा परिसंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन .....

ट्राइबल सब प्लान पर सुझाव दिए और दलितों के उत्थान हेतु बजट में विशेष प्रावधान करने की मांग की। आरक्षण शासन–प्रशासन में दलितों की भागीदारी सुनिश्चित करता है तो एससीपी एवं टीएसपी उनके आर्थिक उत्थान का उपाय है। पिछले कुछ सालों से जिस तरह की गतिविधियां चल रही है उससे एससीपी एवं टीएसपी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। केन्द्र और राज्य स्तर पर मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा एस. सी.पी. एवं टी.एस.पी. के धन को उचित रूप से लागू करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी को समुचित स्टाफ के साथ प्रकोष्ठ बने, जो यह देखे कि अजा/जजा के किन विकास कार्यों पर धन खर्च किया जाना है। एस.सी.पी. /टी.एस.पी. की योजनाओं की गहन निगरानी होनी चाहिए एवं सूचनाएं सार्वजनिक की जानी चाहिए। राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की जानी चाहिए, जिसका कार्य एससीपी नीतियों के निर्धारण, योजनाओं के अनुमोदन, और निगरानी करने की होनी चाहिए। हमारी मांग है कि एससीपी/टीएसपी को लागू करने हेतु एक विस्तृत कानून आंध्र प्रदेश अजा/जजा सब–प्लान विधेयक, 2013 की तर्ज पर संसद में पास होना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में उपजी तमाम कानूनी पेचदियों की वजह से लाखों कर्मचारियों का उ0 प्र0 में डिमोशन हो रहा है। दिसंबर 2012 में लोक सभा में पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए बिल पास ही होने वाला था कि समाजवादी पार्टी ने अवरोध उत्पन्न किया जिससे वह रुक गया। समाजवादी पार्टी की सरकार इस समय उ0 प्र0 में बड़ा अत्याचार कर रखा है, जो अनुसूचित जाति/जन जाति के लोग स्वयं की मेरिट से हेड कांस्टेबल और सब–इंस्पेक्टर बने उनको डिमोट कर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल बनाया जा रहा है। केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह फौरन हस्तक्षेप करे ताकि शोषण से इन्हें बचाया जा सके। निजीकरण एवं भूमण्डलीकरण के कारण रोजगार घटे हैं। चौथी श्रेणी की नौकरियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। उनका निजीकरण किया जा चुका है और ठेकेदारी प्रथा से स्थिति और खराब हो गयी है। ठेकेदारी प्रथा का खात्मा हो और निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के लिए सरकार कानून बनाए। बिना शिक्षा के कोई देश आगे जा नहीं सकता। शिक्षा के निजीकरण के कारण दलित–आदिवासी एवं पिछड़ों के बच्चे ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां पर शिक्षा का स्तर दिन–प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। निजी क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, जो काफी महंगी है। कानून तो है कि सभी को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए लेकिन जब तक समान शिक्षा न हो तब तक इसका कोई मतलब नहीं है।

उन्होंने कहा कि संसद ने 99वां संशोधन किया, जिससे नेशनल ज्यूडिशियल अप्वाइंटमेंट कमीशन का गठन हुआ। दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। दुर्भाग्य है कि इस देश में सवा–सौ करोड़ नागरिकों का फैसला सुप्रीम कोर्ट में बैठे पांच नागरिक अर्थात् पांच जज उलट देते हैं। लगभग 400 जजों का स्थान रिक्त है और जिस तरह से कोलेजियम का व्यवहार है, नहीं लगता कि दलितों, पिछड़ों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस जे.एस. परदीवाल ने आरक्षण और भ्रष्टाचार को एक समान कहा। उन्होंने कहा कि इससे देश बर्बाद हो रहा है। ऐसे जज के खिलाफ महाभियोग चलाया जाना चाहिए। लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, उन्हें विशेष अभियान के द्वारा भरा जाए। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत दिल्ली में गरीबों और दलितों को जमीनें दी गयी थीं, जिन्हें अभी भी भूमिधरी का अधिकार नहीं दिया गया। दिल्ली सरकार ने अनुमोदन कर दिया है, लेकिन गृहमंत्रालय में लंबित है, जो कि फाइल की खानापूर्ति ही होनी है। शिक्षा सबसे ज्यादा विकास की कड़ी है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा दिन–प्रतिदिन गिरती जा रही है। दलित, आदिवासी एवं पिछड़े ही ज्यादातर इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है कि बेहतर शिक्षा निजी संस्थाओं में ले सकें। सरकार ने शिक्षा को अनिवार्य बनाया है लेकिन समान नहीं किया और जब तक समान शिक्षा नहीं होती अनिवार्य करने से भी कोई हल नहीं। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ी है, उस गति से छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। इसलिए इसको बढ़ाया जाना चाहिए। बहुत दिनों से छात्रावास बनने बंद हो गए हैं, जबकि और बनाए जाने चाहिए।

नसोसवाईएफ ने देश के विभिन्न जिलों में रोहित वेमुला की हत्या के विरोध में किया प्रदर्शन

नेशनल एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. स्टुडेंट एंड यूथ फ्रंट (नसोसवाईएफ) ने जंतर-मंतर दिल्ली सहित देश के विभिन्न जिलों में रोहित वेमुला की हत्या के विरोध में और रोहित के इंसाफ के लिए प्रदर्शन किया। रोहित वेमुला, एक पी.एच.डी. छात्र ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के जातीय भेदभाव और शोषण के कारण अत्महत्या की है। रोहित पर आरोप था कि रोहित ने ए.बी.वी.पी. के छात्र नेताओं से मार-पीट की। इसी कारण रोहित और उनके चार साथियों को विश्वविद्यालय के छात्रावास से निकाला गया था। रोहित वेमुला अम्बेडकर स्टुडेंट एसोसिएशन का छात्र नेता था और एक अम्बेडकरवादी छात्र भी। छात्रावास से निकाले जाने के बाद रोहित ने विश्वविद्यालय के बाहर खुले में रहकर जातिवादी विश्वविद्यालय के प्रशासन के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया था। 15 दिनों से चल रहे इस आंदोलन का असर विश्वविद्यालय और कुलपति के प्रशासन पर नहीं होता देखकर रोहित ने आत्महत्या की है। रोहित को जब छात्रावास से निकाला गया था तब रोहित के इंसाफ के लिए

रोहित के आंदोलन में नसोसवाईएफ के आंध्र प्रदेश समन्वयक चेराबंडू राजू और नसोसवाईएफ के कार्यकर्त्ताओं ने रोहित के साथ आंदोलन में शामिल हुए थे। इस आंदोलन में परिसंघ ने भी समर्थन दिया था। देश के सभी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में दलित, आदिवासी छात्रों का शोषण और दमन होता आ रहा है। सवर्ण अध्यापक, प्रशासक और छात्र इन छात्रों के साथ जातीय भेदभाव और वर्ताव करते हैं। अध्यापक आंतरिक परीक्षा में जाति देखकर दलितों को कम अंक और फेल करते हैं तो सवर्ण छात्र रैगिंग के नाम पर दलित-आदिवासी छात्रों को जातीय गाली-गलौच और जानबूझकर शारीरिक और मानसिक यातनाएं देते हैं।

कुल मिलाकर देश के शिक्षण संस्थानों में दलित-आदिवासी छात्रों के साथ तो भेदभाव होता ही है लेकिन सरकार भी इन छात्रों को मिलने वाली भारत सरकार छात्रवृत्ति वक्त पर नहीं देती। विश्वद्यालय और महाविद्यालयों में आरक्षण का बार-बार उल्लंघन होता है, इसलिए बहुत से छात्र शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। दलित-आदिवासी छात्रों की छात्रावास की समस्या गंभीर है। सवर्ण छात्र इन छात्रावासों में दलितों को रहने नहीं देते और सामाजिक न्याया विभाग के छात्रावास छात्रों की तुलना में बहुत कम हैं। आज भी रोहित वेमुला जैसे लाखों छात्र जातीय भेदभाव और शोषण का शिकार हो रहे हैं और सरकार अनदेखी कर रही है। नसोसवाईएफ ऐसे पीड़ित छात्रों के हक के लिए संघर्ष कर रहा है। रोहित की हत्या के खिलाफ नसोसवाईएफ ने आंदोलन खड़ा किया है। इसमें रोहित वेमुला की हत्या की निष्पक्ष जांच हत्यारों को सजा, दलित आदिवासी छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में छात्रावास, भारत सरकार छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी और दलित आदिवासी छात्रों की समस्या पर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर आयोग के गठन की मांग करते हुए देश के विभिन्न राज्यों में आंदोलन शुरु है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में शिक्षण संस्थानों को एक दिन बंद करके स्वा. रा. ती.म. विश्वविद्यालय के सामने छात्रों ने एकत्रित होकर इसकी निंदा की। कोल्हापुर में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने चक्का जाम किया। इस बीच नसोसवाईएफ के छात्रों और पुलिस के बीच नोक-झोंक हुई और 130 कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार भी किया था। हिंगोली जिले में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया गया। मुंबई विश्वविद्यालय में नसोसवाईएफ ने विश्वविद्यालय को एक दिन बंद करके आंदोलन किया। इस बीच विश्वविद्यालय के सुरक्षा रक्षक, प्रशासक ने नसोसवाईएफ के छात्रों पर पत्थर फेंके और गाली-गलौच भी किए। विश्वविद्यालय में तनाव भी बना रहा। अमरावती के संत गाडगे महाराज विश्वविद्यालय के सामने छात्रों ने धरना-प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में जिला खरगोन और बड़वानी में रोहित के इंसाफ के लिए मोर्चा निकाला गया तो खंडवा, छत्तरपुर, भोपाल, टीकमगढ़ में कैंडल मार्च निकालकर छात्रों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बिहार के पटना और भोजपुर में भी छात्रों ने मोर्चा निकाला था। राजस्थान के जिला पाली, कोठा, जालौर में धरना-प्रदर्शन किया गया। पंजाब के लुधियाना में कैंडल मार्च निकाला गया था। इस बीच नसोसवाईएफ के दक्षिण भारत के समन्वयक - सबरी वीरन और शिवा कामले ने हैदराबाद विश्वविद्यालय में जाकर छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। नसोसवाईएफ ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर 25 जनवरी, 2016 को एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन करके राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा।

- डी. हर्षवर्धन

मेडिकल की सीटों में 12,000 करोड़ रुपये की ब्लैक मनी का कारोबार

रेमा नागराजन, नई दिल्ली

आपने किसी आईआईटी और एम्स में कंफर्म ऐडमिशन या सीट बुक करने वाला विज्ञापन नहीं देखा होगा, न ही ऑल इंडिया सिविज सर्विसेज में आपकी पसंदीदा सर्विस में चुने जाने का कोई विज्ञापन देखने को मिलता है। बावजूद इसके देश भर के मीडिया में एमबीबीएस सीट के विज्ञापनों की भरमार रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ऐडमिशन मेरिट के आधार पर होता है तो कोई डायरेक्ट ऐडमिशन का वादा कैसे कर सकता है?

देख लो आरक्षण विरोधियो आपके लोग योग्य न होते हुए भी चोर दरवाजे से कैसे आरक्षण पाते हैं। 422 मेडिकल कॅलेजों में से 224 प्राइवेट हैं। इनमें MBBS की 53% सीटें रहती हैं। इनमें कई का हाल तो ऐसा है कि यहाँ न तो मरीज है और न ही फेकल्टी... फिर भी MBBS की एक सीट की कीमत बेंगलुरु में 1 करोड़ तथा UP में 25 से 35 लाख होती है। रेडियोलोजी और डर्मोटोलोजी की एक सीट की कीमत 3 करोड़ तक है। जिस अयोग्यता की दुहाई देकर आप लोग वैधानिक आरक्षण का विरोध करते हो। क्या आपको यह अपना अवैधानिक 100% आरक्षण दिखाई नहीं देता है।

आपको बताते हैं कि इस वादे के पीछे प्राइवेट कॉलेजों की मेडिकल सीटों का ब्लैक मार्केट है। कॅलेज मैनेटमेंट और एजेंट मिलकर प्राइवेट कॅलेजों में 30 हजार से ज्यादा एमबीबीएस और करीब 9,600 पीजी की सीटें बेचने का काम करते हैं। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इन सीटों में हर साल करीब 12 हजार करोड़ रुपये की ब्लैक मनी इधर से उधर होती है।

भारत में 422 मेडिकल कॅलेज में से 224 प्राइवेट हैं। इनमें एमबीबीएस की 53 फीसदी सीटें रहती हैं। इसमें से कई कॅलेजों में काफी कम सुविधाएं हैं। इनमें से कई का हाल तो ऐसा है कि यहां न तो मरीज हैं और न ही फैकल्टी। इसी एमबीबीएस की एक सीट की कीमत बेंगलुरु में 1 करोड़ रुपये और यूपी में 25 से 35 लाख रुपये होती है। रेडियॉलाजी और डर्मटॉलाजी की एक सीट की कीमत 3 करोड़ रुपये तक है।

इन सीटों के लिए पहले आओ-पहले पाओ का प्रावधान होता है। पहले से बुक करने पर आपको कुछ छूट भी दी जाती है। हालांकि एक बार मेडिकल प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित होने पर प्राइवेट कॉलेजों में सीटों की कीमत दोगुनी हो जाती है। केवल एमबीबीएस की सीटें हर साल 9 हजार करोड़ रुपये में बिकती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज अपने एंट्रेंस एग्जाम खुद कराने का दावा करते हैं ताकि मेरिट के आधार पर छात्रों का चयन हो। हालांकि कई राज्यों में इसका खुलासा हो चुका है कि पैसे वाले उम्मीदवारों को कम नंबर आने या एग्जाम में नहीं बैठने पर भी सीटें मिल जाती हैं। मेरिट वाले कई छात्रों को जबरन बाहर निकाला जाता है या किसी बहाने से बाहर कर दिया जाता है।

आपको बता दें कि ज्यादातर राज्यों में कॉलेज 15 फीसदी सीटें एनआरआई कोटे के लिए रखते हैं। असल में ये सीटें भी बेची जाती हैं। इससे कहीं 50 तो कहीं 80 और कहीं-कहीं तो 100 फीसदी सीटें बेच दी जाती हैं। यह आंकड़ा हर राज्य में अलग-अलग होता है। एमपी और महाराष्ट्र में मैनेजमेंट कोटा 43 फीसदी है, इसमें एनआरआई कोटा मिला देने पर कुल 60 फीसदी तक हो जाता है। मेडिकल की पोस्ट ग्रैजुएशन सीटें करीब 23,600 हैं, इसलिए इनकी मांग और भी ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर में 9,400 सीटें हैं, जिसमें 1,300 डिप्लोमा सीट हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार इसमें से 40 फीसदी सीटें बेची जाती हैं। पीजी की सीटों की कीमत ही करीब 2,900 करोड़ रुपये है। प्राइवेट सेक्टर में 370 सुपर-स्पेशलाइजेशन सीटें हैं, जिसमें से भी 40 फीसदी बेची जाती हैं। इस तरह एमबीबीस के बाद की पढ़ाई का ब्लैक मार्केट करीब 3,000 करोड़ रुपये का है, जो कुल मिलाकर 12 हजार करोड़ रुपये का बैठता है। यह सारी रकम कैश में दी जाती है। खुलेआम यह सब होने के बावजूद सरकार ने अभी तक इस मामले में न तो कोई कार्रवाई की है और न ही इसे रोकने को कोई कदम उठाया है।

http://navbharattimes.indiatimes.com/india/Black-money-quota-25000-MBBS-PG-seats-at-Rs-12000-crore/articleshow/50780717.cms?prtpage=1

✦✦✦

How Australia can help "Clean India" to achieve ambitious goals

Stephen Manallack
(Australian Author)

When Indian Prime Minister Narendra Modi launched "Swachh Bharat" (Clean India) in October 2014 he set three targets which Australian business can help India to reach – massive construction program for toilets especially in villages and schools, applying modern municipal solid waste management and changing attitudes and creating awareness of health and cleanliness.

These are all areas where Australia has expertise with the announcement late last year of a US$1.5 billion loan from the World Bank, the program will increase in 2016. As the World Bank found, of the 2.5 billion people on the planet lacking access to proper sanitation, some 750 million live in India and of these 80% are rural. For them, open defecation is the only option.

Modi has committed to achieving his Clean India goals by 2019 – the 150th anniversary of the birth of Mahatma Gandhi.

Waste management is complex, because there is a whole sector of the population who earn from sorting through mountains of waste.

Most of those engaged in sorting waste are Dalits (previously known as untouchables) and Adivasis (tribal) and the leading politician working for them is Udit Raj, age 55, a lifetime fighter of injustice and defender of the downtrodden.

Udit Raj has made his way to the centre of Indian politics, with a belief that this is how he can impact most change. He recently joined Modi's ruling BJP Party.

Prior to the last election he said: "When Shri Narendra Modi becomes the Prime Minister, Dalits and Adivasis will not only get participation in governance but we shall be equal partners in ushering in a prosperous and strong India."

The first thing the Australian waste management industry should do is get over to India, meet and learn from Udit Raj and explore all aspects of Clean India.

As a nation we should also think about creating some youth groups who get over there as volunteers to help with the clean-up in many ways. To do this we should seek the advice and support of Lakshyaraj Singh Mewar, the 31 year old who is the current custodian of a dynasty – the 1,500 year old House of Mewar, the oldest continuous dynasty in the world. Lakshyaraj Singh Mewar is an Executive Director of the HRH Group (Historic Resort Hotels) which own the largest collection (at least ten) of privately owned heritage palace hotels "where once the Maharanas of Mewar held court".

This could be backed by banks, IT firms or any corporation engaged with India - this is not just for waste management - consider that India's biggest IT firm TCS has signed on to a major toilet building program as part of Clean India. Time for us to think outside the square.

Lakshyaraj is a community campaigner, lending his name and personal effort to causes for education, health, environment and other social causes. His mantra is straightforward – "Don't talk, just act. Don't say, just show. Don't promise, just prove".

Time for the Australian waste management industry to act, show and prove.

Stephen Manallack is a Director of the EastWest Academy, leading Australian trade missions and engagement with India, and the author of three books including "Soft Skills for a Flat World" published by Tata McGraw-Hill India in December 2012 - providing insights into the "10 mindsets" of Indian business. He serves on the Judging Panel for the Annual Business Awards of the Indian Executive Club in Melbourne. He is currently preparing COMMUNICATING YOUR PERSONAL BRAND book and training programs.

EMAIL
stephen@manallack.com.au

https://www.linkedin.com/pulse/how-australia-can-help-clean-india-achieve-ambitious-goals-manallack

✦✦✦

Do you cultivate future leaders of India? Here are 3 to watch

Stephen Manallack
(Australian Author)

Who are the next generation of Indian political leaders? For business and Government outside of India, it is vital to develop relationships now with those who will take the lead later, whether as politicians or centres of influence.

Do you want to participate in Modi's big schemes for Clean India, Digital India, Smart Cities and more? Is access to middle class Indians the key for your product or service? Do you want to plan for the next generation of Indian middle class?

When you consider that the BJP government of Prime Minister Narendra Modi has four years until possible re-election, preparing for generation change makes good political and business sense.

Of the many potential future leaders, I would focus on three who are very different from each other – each poised to take a step up in India's leadership, while already highly significant and influential in their current posts. The three are Om Prakash Mathur, Udit Raj and (Prince) Lakshyaraj Singh Mewar.

Om Prakash Mathur

Known as Om Mathur, aged 64, current Member of Parliament (Rajya Sabha) for Rajasthan State, he is also National Vice President of the Bharatiya Janata Party (BJP) of Prime Minister Narendra Modi. Having spent over six years as party official in charge within Modi's state of Gujarat, Mathur has built a close relationship with Modi who was then Chief Minister and now as PM.

In 2014 he was seen as a frontrunner for the National Presidency of BJP, but was pipped by close friend and ally Amit Shah. Being close to both Modi and Shah is a major plus, as is his reputation as a political organiser and administrator. He was recently given the major assignment of heading the BJP in Uttar Pradesh with the task of winning a really tough election there in 2017. Still, he headed the BJP in the state of Maharashtra and they had their first win there, so he is a formidable planner, known for organisational skills and motivator of party volunteers.

Om Mathur is a big believer in building young membership of the party: "We have to make our youth power active by rising above caste and religion and concentrating on making the country strong in economic and other matters". He is known as a politician who "accepts challenges" and for this he is certainly on the way further up.

Udit Raj

Udit Raj, age 55, is a lifetime fighter of injustice and defender of the downtrodden – in India this means he has been a champion of the Dalits (once known as untouchables and either at or below the bottom of the old caste system) and the Adivasis (which are tribal Indians). Udit Raj has made his way to the centre of Indian politics, with a belief that this is how he can impact most change. He recently joined the ruling BJP Party and explains why – "After Independence, the reins of power have mostly been in the hands of the Congress Party. Even after sixty-six years of Independence, there has not been any significant change in the socio-economic life of Dalits and Adivasis."

Prior to the last election he said: "When Shri Narendra Modi becomes the Prime Minister, Dalits and Adivasis will not only get participation in governance but we shall be equal partners in ushering in a prosperous and strong India."

There are 170 million Dalits and 100 million Adivasis – which also means Raj has quite an electoral base. With change this group increasingly will find employment, becoming part of a rising economy, with disposable income and aspirations. Udit Raj is the man to lead them to these aspirations, and it seems he knows the key to making change is to be influential at the centre of politics – which means key positions could be around the corner.

One factor for business and government wanting connections and advice in Delhi – he lives there, his electorate is there and he has a lifetime of lobbying there.

Lakshyaraj Singh Mewar

He is 31 years old and the current custodian of a dynasty – the 1,500 year old House of Mewar, the oldest continuous dynasty in the world. Lakshyaraj Singh Mewar is an Executive Director of the HRH Group (Historic Resort Hotels) which own the largest collection (at least ten) of privately owned heritage palace hotels "where once the Maharanas of Mewar held court".

Headquarters is the amazing lakeside city of Udaipur founded by the legendary Pratap Singh (16th century), a forbear of Lakshyaraj who refused to surrender to the Mughals and created a strategically placed and sustainable city much admired today.

This young man has worked rather than being gifted titles – he studied in Australia at the Blue Mountains International Hotel Management School and in Singapore at Nanyang University. He worked in the Four Seasons Hotel and various cafes in Sydney, gaining experience which he has used to add value to the heritage hotels in India.

Lakshyaraj is a community campaigner, lending his name and personal effort to causes for education, health, environment and other social causes. His mantra is straightforward – "Don't talk, just act. Don't say, just show. Don't promise, just prove".

He has been made a President of the Udaipur District Cricket Association, an Advisor to the President of the Rajasthan Cricket Association and has won several hotel industry awards including Young Achievers Award of 2015.

What is next for him? Perhaps it will be politics? Maybe a role as a global ambassador for the history and heritage of India? Perhaps a trade, investment and tourism advocate in the way Prince Charles has been for the UK? Business and government with an interest in closer ties with India would well consider him as one potential and influential link. He will make the future choice with care – "Taking a step is easy. Taking the right step is what's important."

For business and government outside of India, it is vital to develop relationships now with those who will take the lead later, and these three should be on your list.

Stephen Manallack is a Director of the EastWest Academy and the author of three books including "Soft Skills for a Flat World" published by Tata McGraw-Hill India in December 2012 - providing insights into the "10 mindsets" of Indian business. He serves on the Judging Panel for the Annual Business Awards of the Indian Executive Club in Melbourne. He is currently preparing COMMUNICATING YOUR PERSONAL BRAND book and training programs.

EMAIL
stephen@manallack.com.au

https://www.linkedin.com/pulse/do-you-cultivate-future-leaders-india-here-3-watch-stephen-manallack

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 19 ● Issue 5 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 16 to 31 January, 2016

Dr. Udit Raj's Birthday celebrated on 26 Jan

Shri Ravishankar Prasad, Cabinet Minister at the Function

Shri Ram Vilas Paswan, Cabinet Minister at the Function

Shri Vijay Sampla, Minister of State at the Function

Gen.(Retd.) V. K. Singh, Minister of State at the Function

Vladimir Maric, Ambassador of Serbia with his wife

Ambassador of Algeri Hamza Yahi Sharif at the Function

Dr. Udit Raj, Member of Parliament (Lok Sabha) celebrated his birthday on 26th January 2016 at a glittering function hosted by his wife, Mrs. Seema Raj, Commissioner of Income Tax, Delhi. The function was attended by Shri Ravishankar Prasad, Hon'ble Minister of Information Technology and Communication, Shri Ram Vilas Paswan, Hon'ble Minister of Consumer Affairs and Public Distribution, Gen(Retd.) V K Singh, Hon'ble Minister of State of External Affairs and Shri Vijay Sampla, Hon'ble Minister of State of Social Justice and Empowerment. Other dignitaries at the celebrations included the Ambassador of the Republic of Serbia to India His Excellency Vladimir Maric, the Ambassador of Algeria to India His Excellency Hamza Yahi Sharif, the Ambassador of Romania to India as well as representatives from the Embassies of Sweden, Italy, Japan, United States of America and the Kingdom of Saudi Arabia. Several other dignitaries also attended the function at Chattarpur farms including Shri Arun Goel, IAS, Vice Chairman, DDA, Shri R K Srivastava, IAS, Chairman, Airports Authority of India, Shri Atul Srivastava, DIG Intelligence, Railway Board, Shri Kazem Samandari, CEO, Terrafirma International and his wife Christina Samandari, CEO, La Opera, Shri R Wanchoo, Chief General Manager, NBCC, a team from Bharti Foundation and Shri Tony Castleman, Country Head, Catholic Relief Services.

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya